

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 24, मार्च, 2014

विषय— उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक 2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या-05/उ0आ0वि0परि0/बी0एम0-13-14, दिनांक 03 जनवरी, 2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून के अधिष्ठान हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि कम के कारण संलग्नक बी0एम0-15 में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 4,00,000/- (रु0 चार लाख मात्र) की धनराशि को अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में पुनर्विनियोग द्वारा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा और उक्त मदों में अब तक इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जायेगा।

3— स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार उन मदों पर ही किया जायेगा तथा देयता के निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

4— आवंटित बचत की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 तथा प्रपत्र बी0एम0-13 पर सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5— व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, अधिप्राप्ति नियमावली, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6— अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-3-2014 तक सुनिश्चित कर लिया जाये।

7— उक्त व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों तथा वित्त विभाग के पत्र संख्या-284/xxvii(1)/2013, दिनांक 31 मार्च, 2013 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत किये जा रहे हैं।

8— व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह व्यावर्तित किया जा रहा है।

9— पी0आर0डी0 कार्मिकों के मानदेय का भुगतान, मा0 अध्यक्ष के स्टाफ का पारिश्रमिक, वाहन का किराया तथा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में अधिवक्ता की फीस का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप नियमानुसार किया जाएगा।

10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य-07-00-उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-808/xxvii(2) /2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोक्त ।

भवदीय.

(डी०एस० गब्र्याल)
सचिव ।

संख्या : 354, (1) / V-2-102(आ0) / 14-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- अपर आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 4- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डॉ० शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव ।

(वित्तीय वर्ष 2013-2014)(भाग-एक)
बी0एम0-09

अनुदान संख्या व नाम-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास
मुख्य शीर्षक 2217-शहरी विकास
80-सामान्य-00-आयोजनेतर-800-अन्य-
07-उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद

(धनराशि हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाय				निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरे जायेंगे।			
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	आवेदन को तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचत	अंतरित की जाने वाली राशि	अंतरण के अवशेष अनुदान / विनियोग (2-5)	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि
2217-शहरी विकास 80-सामान्य-00-आयोजनेतर-800-अन्य-07-उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद								2217-शहरी विकास 80-सामान्य-00-आयोजनेतर-800-अन्य-07-उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद							
01-वैतन	3200	2317	400	2300	400			16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	700	400	400		400	1100	

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

सेवा में,

(महालेखाकार ए एंड ई)
उत्तराखण्ड, औद्योगिक बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
देहरादून।

(डा0 शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव।
वित्त विभाग

- संख्या: / 2014- तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1 जिलाधिकारी, देहरादून।
2 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3 अपर आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
4 वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
5 एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6 गार्ड बुक।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2013-2014)
बी.एम. - 09

पत्र संख्या - 013
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या -

बजट नंबर - R1403130265
दिनांक - 12-Mar-2014

क्र. संख्या	बजट शीर्षक का प्रारंभिक (1)	आवक संशोधन (2)	वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित व्यय (3)	आवक संशोधन बजट (4)	मेमोरीज्ड बजट में आवक की कमी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद व्यय -5 की कुल बजट (6)	पुनर्विनियोग के बाद व्यय -1 के कुल बजट (7)	(In Rupees) अंशित
	2217 बहुरी विकास 80 सामान्य 800 अन्य 07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद 00 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद (Non Plan Voted)				2217 बहुरी विकास 80 सामान्य 800 अन्य 07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद 00 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद (Non Plan Voted)			
1	01 - बजट 3200000	1051470	1738530	400000	*8 - प्राथमिक एवं द्वितीय लेवल 400000	1150000	2800000	
	बीस			400000	बीस 400000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राधिकारों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेक्टर 23- लक्ष्मी रोड बालनबाला, देहरादून को उपलब्ध करायी

(अरुणेंद्र सिंह चौहान)
उपर सचिव-वित्त
उत्तराखण्ड शासन